**Demand to withdraw 5% GST imposed on finished mat made of sticks, an agricultural product**

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA (West Bengal): Sir, mat stick is an agricultural product. Lakhs of people all over different States, including majority percentage in West Bengal, have been growing agricultural mat sticks in their own land. After preparing their mat sticks, people, mostly women, from the age group of 12 years to 80 years, usually prepare complete mats of different qualities. Then these prepared mats of different qualities are sold to businessmen in the rural markets of blocks and districts. Other unemployed youths are selling these mats in different district headquarters and cities to earn their livelihood. Fifty-two per cent of the natural agricultural mats are produced in Sabaug block in the district of Paschim Medinipur in West Bengal. The Central Government and the GST Council have imposed 5 per cent GST on finished and prepared mat when it comes in the market for sale. This has created a tremendous financial strain on mat marketing affecting the artisans and mat stick growers. The 5 per cent GST imposed on mat should be withdrawn for the benefit of poor mat growers mat artisans and poor mat traders.

**श्री उपसभापति** : श्री राजमणि पटेल जी।

**Demand to pay equal remuneration to the faculty and staff working in Ayush and Allopathic medical colleges**

**श्री राजमणि पटेल** (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति निश्चित रूप से हमारे देश के गांव और गरीबों के लिए एक वरदान पद्धति है।

**श्री उपसभापति** : राजमणि पटेल जी, जो लिखा हुआ है, उसी को पढ़ें।

**श्री राजमणि पटेल** : उपसभापति महोदय, आयुष चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों तथा प्राचार्यों को एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों के समान वेतनमान एवं भत्ता नहीं दिए जाने से व्यापक असंतोष व्याप्त है। माननीय उपसभापति जी, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्राध्यापक की तुलना में आयुर्वेद महाविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापक को ग्रेड पे 1,600 रुपए कम मिल रही है, 4,000 रुपए विशेष भत्ता भी नहीं मिल रहा है। इसी तरह सहायक प्राध्यापकों को 5 वर्ष बाद भी ग्रेड पे 2,600 रुपए कम तथा 4,000 रुपए विशेष भत्ता भी नहीं मिल रहा है। 8 वर्ष बाद भी दो गुना वेतन एवं 5,000 रुपए विशेष भत्ता नहीं मिल रहा है। सह प्राध्यापक के पद पर ढाई गुना वेतन एवं 5,000 रुपए विशेष भत्ता वेतन नहीं मिल रहा है।

[श्री राजमणि पटेल]

महोदय, प्राध्यापक के पद पर भी चिकित्सा महाविद्यालयों की तरह ढाई गुना स्केल एवं 6000 रुपए विशेष भता आयुर्वेद महाविद्यालय में नहीं मिल रहा है। अधिष्ठाता/प्रधानाचार्य के पद पर भी इसी तरह न तो ढाई गुना स्केल मिल रहा है और न ही 9000 रुपए विशेष भता दिया जा रहा है।

महोदय, देश के कई प्रदेशों में चिकित्सा महाविद्यालय एवं आयुष महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन मान एवं सुविधा में अंतर है। मध्य प्रदेश में शासकीय आयुष आयुर्वेदिक होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा में इस तरह की व्यवस्था से महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों में व्यापक असंतोष है।

मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि आयुर्वेद के महत्व तथा आवश्यकता को देखते हुए आयुर्वेद चिकित्सा को प्रोत्साहन देने की नीयत से चिकित्सा महाविद्यालयों की तरह आयुष महाविद्यालय एवं संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी वेतनमान एवं सुविधा प्रदान करने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

**श्री उपसभापति** : माननीय राजमणि पटेल जी आपके कुछेक शब्द नए पढ़े, जो approved text में नहीं हैं। आपको जो स्वीकृत Special Mention मिला, वह ही पढ़ा जाना है, अन्य शब्द रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगे।

**Demand to protect and rejuvenate the wetlands**

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, wetlands are natural or human-made ecosystems in which the soils are waterlogged or inundated periodically or permanently under water of varying depths, which allows the development of characteristic aquatic vegetation and fauna. Across the country, river floodplains, shallow lakes, ponds, marshes, swamps, coastal waterbodies, mangrove systems and even coral reefs are counted amongst wetlands. Amongst other things, wetlands regulate flooding, host biodiversity, maintain fish nurseries, protect coastal areas against storms as well as from saline ingress in ground waters, allow for aquatic farming and fisheries.

The systemic and rapid loss of wetlands across the country due to various man-made factors like excessive hydrological alterations, unregulated construction and haphazard urbanization, and the disposal of wastes, is a major cause of ground water depletion and increased flooding. Although 27 Indian wetlands of different kinds have been designated as 'Internationally Important' under the Ramsar Convention, most of them have no management plans and are in different states of degradation. Despite judicial interventions, wetlands have not yet received due protection. Indian wetlands need to be systematically delineated and mapped based on revenue records and their hydrological features need to be listed and notified at district or block level. Buffer areas must be demarcated and certain activities need to be prohibited. For ensuring